विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के पुस्तकालयों में हिन्दी साहित्य

820. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम दूतावासों को भेजा जा रहा है ; यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) दूतावासों के पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तकों और हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की स्थिति क्या है और क्या दूतावासों में राजभाषा की उपेक्षा की जा रही है ;

(ग) क्या वहां राजभाषा में कार्य करने की सुविधा के लिये टेलीप्रिंटर, टेलेक्स, कम्प्यूटर इत्यादि उपलब्ध कराने के कोई प्रबंध किये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह): (क) मंत्रालय राजभाषा विभाग तैयार किए गए हिन्दी के प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम की एक प्रति हर वर्ष अपने मिशनों को भेजता है।

(ख) पिछले कई वर्षों से मंत्रालय अपने मिशनों को पत्रिकाएं तथा भारतीय साहित्य, संस्कृति, धर्म इत्यादि जैसे विषयों पर मानक हिन्दी पुस्तकें भेजता रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय मिशनों के अनुरोध पर उन्हें हिन्दी की पाठ्य पुस्तकें तथा अन्य सहायक साहित्य भी भेजता है।

मंत्रालय अपने मिशनों को समय-समय पर राजभाषा से संबंधित सरकारी आदेश भेजता रहता है जिनमें उन पर उनके सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। राजदूतावासों में राजभाषा की उपेक्षा नहीं की जा रही है, हमारे मिशन मुख्यालय के साथ पत्राचार में यथासंभव हिन्दी का प्रयोग करते हैं।

(ग) और (घ) अभी तक इस प्रकार की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। तथापि, जब भी इस प्रकार की आवश्यकता महसूस की जाएगी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

देवघर (बिहार) का एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास

821. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आवश्यक परिवहन सुविधायें और आने वाले पर्यटकों के लाभ के लिये आवास की सुविधायें उपलब्ध करा कर बिहार में देवघर नामक स्थान को एक पर्यटक महत्व के स्थल के रूप में विकसित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार रखती है

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद): देवघर को विकसित करने के बारे में राज्य सरकार से केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को विचार करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, देवघर सड़क और रेल से भली-भांति जुड़ा हुआ है और यहां आवास सुविधा के रूप में दो पर्यटक बंगले हैं तथा काफी संख्या में प्राइवेट होटल भी उपलब्ध हैं।

Income-Tax raids in Delhi

822. SHRI SHAMIM AHMED SIDDIQI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that income-tax raids were conducted in Delhi during the years 1983-84 and 1985-86; and

(b) if so, what was the number of raids conducted and the quantum of black money detected as a result of these raids?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) Yes, Sir. The Income-tax

Department had conducted searches in Delhi as under:—

Year	No. of searches	Value of seizures (Rs. in crores)
1983-84	332	2.11
1985-86	561	4·21

Review of textile policy

823. SHRI A G. KULKARNI:
SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the Secretary's Committee appointed to draft textile policy considered the conclusions drawn by the Ashok Mehta Committee regarding cost handicaps in favour of powerlooms; if not, what are the reasons therefor; and

(b) whether Government propose to call for fresh evidence for the reappraisal of the textile policy in view of widespread resentment among cotton growers' organisations and cotton and silk powerloom organisations?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) The Hon'ble Members of Parliament perhaps refer to the Expert Committee under the Chairmanship of the then Secretary, Ministry of Textiles set up by Government on 12-10-84 to go into the problems of textile industry and suggest measures for its growth and development in a longer term perspective. The Committee examined all aspects covering the three sectors (mills, handlooms and powerlooms) of the textile industry and made a set of recommendations, which *inter-alia* formed the basis of formulation of the new Textile Policy of June, 1985.

(b) No, Sir.

Damaged and torn currency notes

824. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many banks are passing off damaged and torn currency notes to unwary public;

(b) whether it is also a fact that most of the banks are refusing to accept such currency notes; and

(c) if so, whether Government propose to ensure that soiled and torn currency notes are withdrawn by the banks and given to the Reserve Bank for destruction as was the practice in the past?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) Reserve Bank of India have reported that a few complaints were received that some bank branches issue excessively soiled and even cut-torn notes to the public. Instances of some branches refusing to accept damaged/torn currency notes have also come to the notice of Reserve Bank of India. Such complaints are taken up by the Reserve Bank of India with the concerned banks for remedial action.

(c) As and when soiled and torn currency notes are received in the branches of banks acting as agents of Reserve Bank, they are retained by them and are periodically remitted to Reserve Bank of India offices for examination and eventual destruction.